दैनिक जनसेवा मेल
सेवा ही सत्य है
जनसेवा मेल No. 1
झां

राजनैतिक इच्छा शक्ति की कमी औद्योगिक शून्यता की वजह : खण्डेलवाल

संवाददाता, जनसेवा मेल

- फूड सेफ्टी एक्ट को भारतीय स्टैण्डर्ड का बनाने हेतु छिड़ेगा आन्दोलन
- नॉन कॉरपोरेट सेक्टर के वित्तीय सशक्तिकरण हेतु कमर कसी
- रायशुमारी हेतु दस गोल मेज सम्मेलन व तीस जन अदालतें लगेंगी

एक्शन कमेटी फॉर फॉर्मल फाइनेंस फॉर नॉन कॉरपोरेट स्माल बिजनेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर प्रवीण खण्डेलवाल ने स्वीकारा कि बुन्देलखण्ड में जमीनों की कीमतें तो नोएडा की बराबरी कर रहीं, किन्तु औद्योगिक शून्यता ने बेरोजगारी व पलायन को चरम पर पहुंचा दिया है। इससे बुन्देलखण्ड से पिछड़ेपन का दाग साफ होने का नाम नहीं ले रहा। उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि राजनैतिक इच्छा शक्ति की कमी से बुन्देलखण्ड में जहां औद्योगिक विकास के नाम पर शून्यता है, वहीं पर्यटन उद्योग को भी दीमक लग गया है, जबकि प्राकृतिक सम्पदा, औद्योगिक क्षेत्र, संसाधन व देश को चारों दिशाओं से जोड़ने वाले मार्गों से बुन्देलखण्ड सम्पन्न है।

यहां भामाशाह सम्मान समारोह में आए प्रवीण खण्डेलवाल को जब पत्रकारों ने बुन्देलखण्ड के औद्योगिक विकास के मुद्दे पर घेरा तो उन्होंने आश्वस्त किया कि व्यापारी संगठन भी बुन्देलखण्ड के औद्योगिक विकास के मुद्दे पर सकारात्मक कदम उठाएगा और इसके परिणाम शीघ्र ही दिखाई देने लगेंगे। इसके लिए उन्होंने उप्र उद्योग व्यापार मण्डल के प्रदेश अध्यक्ष संजय पटवारी को दिशा निर्देश दिए। व्यापारियों के साथ बढ़ रही लूट, चोरी व डकैती सहित अन्य प्रकार की घटनाओं के विरोध हेतु व्यापारी संगठनों की भूमिका को और सशक्त बनाने व बाजारों में पीपीपी मॉडल पर बाजारों में सुरक्षा नीति की वकालत की।

इस दौरान फूड सेफ्टी स्टैण्डर्ड एक्ट को भारतीय स्टैण्डर्ड का बनाने के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका स्वरूप नहीं बदला, तो पूरे देश में आन्दोलन छेड़ा जाएगा और इसके लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री से वार्ता की जाएगी।

उन्होंने जीएसटी का समर्थन तो किया, पर पूरे देश में उसके एक समान कानून व केन्द्रीय बिक्री कर की वकालत की। व्यापारी नेता ने भाजपा सरकार को व्यापारी हितैषी निरूपित करते हुए पिछली सरकार में कॉरपोरेट सेक्टर को मिले बड़े वित्तीय लाभ व नॉन कारपोरेट सेक्टर की उपेक्षा को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि अब नॉन कारपोरेट सेक्टर ने सरकार से वित्तीय संसाधनों को पाने के लिए कमर कस ली है क्योंकि राष्ट्रीय जीडीपी में सबसे अधिक योगदान व रोजगार देने वाले असंगठित क्षेत्र को वित्तीय कर्ज देने में बैंक व सरकार बुरी तरह से असफल हुए हैं। इसके बावजूद अर्थ व्यवस्था के हर क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र कॉरपोरेट सेक्टर से काफी आगे निकल गया है।

झांसी। पत्रकारों से वार्ता करते व्यापारी नेता।

खण्डेलवाल ने केन्द्रीय वित्त मंत्री से नॉन कॉरपोरेट छोटे व्यापार के विकास हेतु सुदृढ़ व्यवस्था बनाने हेतु एक्शन कमेटी में नॉन कॉरपोरेट स्माल बिजनेस के सभी प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधियों को शामिल करने की मांग की।

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने बताया कि एक्शन कमेटी में शामिल संगठनों की जानकारी देते हुए स्माल बिजनेस फाइनेंस कम्पनी का गठन करने पर जोर दिया। कैट के राष्ट्रीय चेयरमैन महेन्द्र शाह ने नॉन कॉरपोरेट सेक्टर की ऋण की जरूरतों को पिछली सरकारों द्वारा नजरअन्दाज करने का आरोप लगाया और बताया कि देश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर व स्वावलम्बी बनाने के लिए इस सेक्टर की ऋण की जरूरतों पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। कैट के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रमेश खन्ना ने बताया कि नॉन कॉरपोरेट सेक्टर की मजबूती हेतु एक्शन कमेटी अगले दो माह में देश में व्यापक अभियान शुरू करेगी।

व्यापारी नेताओं ने बताया कि बैंकिंग व वित्त विशेषज्ञों, अर्थ शास्त्रियों व अर्थ व्यवस्था से जुड़े लोगों के साथ देश में दस गोल मेज सम्मेलन होंगे। झांसी सहित विविध राज्यों में 30 जन अदालतें लगा कर रायशुमारी लेकर उसके आधार पर श्वेत पत्र तैयार कर उसे प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों व सांसदों को दिया जाएगा। अन्त में बिजनेस डेवलपमेण्ट ऑर्गनाइजेशन के चेयरमैन आनन्द मिश्रा व संरक्षक प्रो. एसआर गुप्ता ने आभार व्यक्त किया।